

मुख्य समाचार

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किए प्रदान—इंदौर पहले स्थान पर बरकरार।
- स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला दो पायदान और फिसलकर 3 सौ 47वें स्थान पर पहुंचा।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—वनभूमि से अवैध कटान की मुहिम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा—सराज में आधारभूत सुविधाएं जल्द हों बहाल।
- प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय—मौसम विभाग का आज 8 जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट।

राष्ट्रपति स्वच्छ सर्वेक्षण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि स्वच्छता देश की सांस्कृतिक चेतना का आधार है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 पुरस्कार प्रदान करते हुए यह बात कही। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल पहल साबित हुई है।

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार आठवें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। इस वर्ष पाँच विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में सुपर स्वच्छ लीग शहर और शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहरों सहित चार श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। इस बीच स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला दो पायदान और फिसलकर 3 सौ 47वें स्थान पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़छम वांगतु पन बिजली परियोजना में रॉयल्टी को लेकर हिमाचल के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार को अब इस प्रोजेक्ट से 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी जिससे सालाना दो सौ 50 करोड़ रुपए की आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात कर आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है।

हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। यह तो होगा हमारा सारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से लेकिन एक चीज और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कारक वर्क कर का मिलना चाहिए वो नियम और कानून के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होने चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो क्योंकि यहां की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है।

हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा, यह तो होगा हमारा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट मिलना चाहिए, वो नियम और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होना चाहिए, जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहां की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। मुख्यमंत्री ने वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने के नाम पर फलदार पौधों को काटने का विरोध किया और कहा कि सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है।

बागवानी के मामले में जो फल से लगे सब काटे जा रहे हैं। हमारी सरकार उसे पक्ष में नहीं। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए और मैं भी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा एक बैठक

बुला रहा हूं मैं और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या, किन आधार पर जाना है सब कानूनी पहलुओं के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस संगठन में कोई फेरबदल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों और अवैध कब्जे हटाने की मुहिम से प्रभावित सेब बागवानों को राहत देने का है।

मेजर जनरल

हमीरपुर के रहने वाले आदर्श वर्मा ने भारतीय सेना में मेजर जनरल के रूप में कमान संभाली है। विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर जनरल आदर्श वर्मा ने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना की अग्निवाज डिवीजन में इस पद की कमान संभाली। कमान संभालते ही मेजर जनरल आदर्श वर्मा ने सैन्य अधिकारियों व जवानों से कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने, भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तैयारी रखने और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सैनिक भावना को हमेशा ऊंचा रखे और मिशन के अनुसार प्रशिक्षण को प्राथमिकता दें। आदर्श वर्मा के मेजर जनरल बनने से हमीरपुर में खुशी की लहर है और उनके परिवार, मित्रों और परिचितों में गर्व का माहौल है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदर्श वर्मा की मेजर जनरल पद पर पदोन्नति पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पल बेहद गर्व और प्रसन्नता से भर देने वाला है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने आज मंडी में आपदा राहत व पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़ी आबादी सड़कों, बिजली और पानी से वंचित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री बांटने में सरकार से ज्यादा दानी सज्जनों का योगदान है। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में इंसानियत के नाते बिना किसी भेद भाव के पीड़ितों के साथ खड़े रहने के लिए सभी लोगों का आभार जताया।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आपदा प्रभावित मंडी जिला में स्कूलों और कॉलेजों के मुरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। रोहित ठाकुर आज शिमला में आपदा प्रभावित मंडी जिला में

क्षतिग्रस्त स्कूलों और कॉलेजों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह जल्दी ही मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में आपदा के कारण 2 सौ 19 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इन में से 2 सौ 8 स्कूल आंशिक रूप से और 11 स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

रोहित ठाकुर ने शिक्षण संस्थानों में सामने आ रहे छेड़छाड़ के मामलों पर कहा कि विभाग और सरकार इन मामलों पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है और तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

मौसम

मानसून के सक्रिय रहने से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी वर्षा का क्रम रुक-रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा कुल्लू व मंडी में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा,

किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन, मंडी और शिमला जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अचानक बाढ़ आने की भी चेतावनी दी है। प्रदेश में पिछले दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं के चलते अभी भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक सौ 69 सड़कें, बिजली के 72 ट्रांसफार्मर और 64 पेयजल योजनाएं अवरुद्ध हैं। मॉनसून से जुड़ी घटनाओं में अभी तक प्रदेश में एक सौ 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 35 अन्य लापता हैं।

राजेश धर्माणी

नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुड़ा की कार्यप्रणाली में नवाचार के समावेश पर जोर दिया है। राजेश धर्माण ने आज शिमला में हिमुड़ा के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों के साथ-साथ प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरित पहल को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किए प्रदान-इंदौर पहले स्थान पर बरकरार।
- स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला दो पायदान और फिसलकर 3 सौ 47वें स्थान पर पहुंचा।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा-वनभूमि से अवैध कटान की मुहिम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा-सराज में आधारभूत सुविधाएं जल्द हों बहाल।
- प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय-मौसम विभाग का आज 8 जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट।